CNEWS सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-277
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

बिहार सिटी चीफ

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

बिहार, शनिवार, 11 जनवरी 2025

आज का विचार

आत्मविश्वास के साथ चला गया हर एक कदम जन-हितकारी होता है।'

कौन हैं रिटायर्ड अधिकारी जो सरकार चला रहे...और *DK* टैक्स की वसूली कर रहे हैं ?

नीतीश राज में *RCP* टैक्स के बाद एक और शख्स के नाम पर टैक्स

चन्दन कुमार चौबे . सिटी चीफ

पटना, बिहार में एक और टैक्स डी.के. टैक्स की चर्चा शुरू हो गई है. पहले आरसीपी टैक्स की खूब चर्चा होती थी. विपक्षी दलों के नेता खासकर तेजस्वी यादव नीतीश सरकार में आरपीसी टैक्स वसूली का आरोप लगाते थे.

हालांकि कुछ समय से सरकार में टैक्स वसूली की चर्चा मंद पड़ी हुई थी. अचानक तेजस्वी यादव ने एक नए टैक्स की चर्चा छेड़ कर खलबली मचा दी है.

कौन हैं रिटायर्ड अधिकारी जो चला रहे सरकार ? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि बिहार में न तो *DGP* की चल रही है और न ही मुख्य सचिव की. अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नहीं चल रही है. आज हालात ऐसे हैं कि रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं. तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में सिर्फ चलता है तो ष्ट च टैक्स. बिहार में पूरी तरह से वसूली हो रही है. अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग में हेराफेरी का खेल चल रहा है. काबिल अधिकारियों को साइडलाइन कर दिया गया है. बिहार में अब केवल वसूली गैंग चल रहा है. बता दें, जब आरसीपी टैक्स की बात होती थी, तब मुख्यमंत्री नीतीश के बेहद करीबी आरसीपी सिंह साथ थे. विपक्षी नेता बिना नाम लिए आरसीपी सिंह पर आरोप लगाते थे. तब कहा जाता था कि आरसीपी सिंह ही सरकार चलाते हैं. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वर्ष 2017-2018 में *RCP TAX* का खूब जिक्र करते थे. तब उन्होंने कहा था कि बिहार में अधिकारी कितनी भी गलती कर ले, मामला कितना भी गंभीर हो, लेकिन उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता. क्योंकि उसने 'आरसीपी टैक्स' देने का काम किया है.

हालांकि तेजस्वी यादव ने आरसीपी टैक्स वसूली की चर्चा कर नीतीश कुमार-आरसीपी सिंह को भले ही कटघरे में खड़े करते हों, लेकिन इसका फूल फार्म अलग ही बताते थे. इस बार तेजस्वी यादव ने डी.के. टैक्स वसूली की चर्चा छेड़कर एक रिटायर्ड अधिकारी पर निशाना साधा है.

प्रधानमंत्री आवास के लिए सर्वे का काम शुरू

बिहार के लाखों बेघर परिवारों को मिलेगा अपना घर

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ

पटना, बिहार के लाखों बेघर परिवारों के लिए गुड न्यूज है। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएम आवास) के तहत बेघर परिवारों को पक्के मकान मुहैया कराने के लिए 10 जनवरी से एक नया सर्वे शुरू किया है। इस सर्वे का उद्देश्य उन सभी परिवारों की पहचान करना है जो बेघर हैं या जिनके पास पक्का मकान नहीं है।

यह सर्वे 31 मार्च तक चलेगा और राज्य की सभी पंचायतों को इसमें शामिल किया जाएगा। सर्वे में ग्राम पंचायत के कर्मचारी जैसे असिस्टेंट लेवल के कर्मचारी, पंचायत सेवक और पंचायत सचिव शामिल होंगे। सर्वे के दौरान कर्मचारी घर-घर जाकर परिवारों की आर्थिक स्थिति, उनके पास मौजूद संपत्ति और रहने की स्थिति का आकलन करेंगे।

पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए कुछ विशेष मानदंड तय किए गए हैं। पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार के पास दो पहिया या तीन पहिया वाहन, कोई जमीन या किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सीमा 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य आयकर या व्यावसायिक कर का भुगतान नहीं करता हो।

पिछला सर्वे 2018-19 में हुआ था और उसमें चुने गए 11 लाख लाभार्थियों को अभी तक मकान नहीं मिल पाए हैं। इस बार सरकार का लक्ष्य है कि इस साल 2.40 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाए। पीएम आवास योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1.30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है, जिसमें मनरेगा के तहत श्रम लागत भी शामिल है।

इसके अलावा, राज्य सरकार लाभार्थियों को जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता भी देती है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य उन सभी बेघर परिवारों की पहचान करना है जो इस योजना के तहत पात्र हैं और उन्हें पक्के मकान मुहैया कराना है।

अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को बार-बार अपमानित किया

सम्राट चौधरी बोले- केजरीवाल की गोद में खेल रहा लालू परिवार

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ

पटना, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचल के लोगों को अपमानित करने को लेकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे पूर्वांचल के लोगों को बार-बार अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार और यूपी के लोग कभी भी किसी का बोझ नहीं बनते हैं, बल्कि जिनके साथ ये लोग होते हैं, उनका सौभाग्य होता है। पटना में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह वही केजरीवाल हैं जो कहा करते थे कि बिहार के लोग 500 का टिकट कटवा कर दिल्ली इलाज के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में कुल मतदाताओं की संख्या पटना की आबादी के जितनी है। आज बिहार में एक करोड़ 21 लाख लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान योजना के तहत कार्ड दिया गया है और उनका मुफ्त इलाज करवाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने राजद अध्यक्ष लालू यादव को भ्रष्टाचारी और अपराधी कहा था और आज उन्हीं का परिवार केजरीवाल की गोद में खेल रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने लालू यादव को परमानेंट जेल के अंदर रखने की व्यवस्था कर दी।चौधरी ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल 13 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और लोगों को गुमराह करने का काम किया। वे भ्रष्टाचार चला रहे हैं और शीशमहल स्थापित किया। इसके अलावा बिहार और यूपी के लोगों को बदनाम किया।उन्होंने कहा कि बिहार और यूपी के लोग टैलेंटेड होते हैं और किसी पर बोझ नहीं होते। ये जिनके साथ खड़े होते हैं, वह उनका सौभाग्य होता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव में पूर्वांचल के लोग दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल से अपमान का बदला लेंगे और सत्ता से हटाएंगे।

बिहार के उप मुख्यमंत्री ने राजद अध्यक्ष लालू यादव से भी सवाल पूछा कि दिल्ली चुनाव में वे किसके साथ खड़े हैं? उन्होंने कहा कि केजरीवाल की पार्टी रोहिंग्याओं का नाम मतदाता सूची में जोड़वाना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि देश के विरोधियों का नाम किसी हाल में चुनाव आयोग को मतदाता सूची में नहीं जोड़ना चाहिए।चौधरी ने आगे कहा कि दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों को अपमानित करने वालों से न केवल बिहार और यूपी के मतदाता इस अपमान का बदला लेंगे, बल्कि उनके साथ रहने वाले नेताओं से भी चुनाव में बदला लिया जाएगा।

नीतीश कैबिनेट ने खोला खजाना

सरकार ने 308 ब्लॉक में इस काम के लिए दी 60 अरब की राशि, जानें....

पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगी है. सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रखंड सह अंचल कार्यालय निर्माण के लिए खजाना खोल दिया है. कुल 308 ब्लॉक-अंचल में नया भवन बनेगा. इसके लिए बिहार कैबिनेट ने लगभग 60 अरब की राशि की स्वीकृति दी है.

308 प्रखंड-अंचल कार्यालय का बनेगा नया भवन

बिहार के कुल 246 जर्जर प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन निर्माण के लिए प्रति प्रखंड 16 करोड़ 62 लाख ?10000 एवं 62 भवनहीन प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय परिसर निर्माण के लिए प्रति प्रखंड 30 करोड़ 74 लाख 17000 रू, कुल मिलाकर 59 अरब 94 करोड़ 75 लाख 14 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. बिहार के 26 जिलों के 72 चौक-चौराहों पर यातायात उल्लंघन करने पर ऑटोमेटेड चालान कटेगा. इस काम के लिए सीसीटीवी एएनपीआर कमरों का अधिष्ठापन एवं रख रखाव किया जायेगा. इसके लिए कुल 35 करोड़ 46 लाख 37000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप पश्चिम चंपारण के पथरी घाट से बरवत सेना पथ कुल लंबाई 6.750 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 73 करोड़ से अधिक राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. वहीं शिवहर में भी शिवहर मीनापुर पथ के चौड़ीकरण के लिए 172 करोड़ 76 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है .बिहार पुलिस के सिपाही हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक की भांति बिहार अग्निशमन सेवा के कर्मियों को वेतनमान का लाभ 21 जनवरी 2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किया गया है.

पूर्वी चंपारण के मेहसी में बूढ़ी गंडक नदी की इब्राहिमपुर घाट पर आरसीसी पुल निर्माण के लिए 17 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के क्रम में की गई घोषणा की अनुरूप वैशाली के महुआ अनुमंडल में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण, ताजपुर महुआ संचरण लाइन, ताजपुर में 132 केवी के दो लाइन के निर्माण के लिए 157 करोड रुपए की नई योजना की स्वीकृति दी गई है.

बेली रोड स्थित 60 सेट ऑफिसर्स आवास के लिए 246 करोड़ 23 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख संतोष कुमार को 2 वर्षों के लिए संविदा के आधार पर नियोजन करने की स्वीकृति दी गई है. भोजपुर के पीरो अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में कोर्ट भवन, हाजत भवन एवं अन्य निर्माण कार्य के लिए 34 करोड़ से अधिक राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. पटना सदर अंचल में कुल 1.46 एकड़ भूमि को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय निर्माण के लिए विदेश मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित किया गया है. पटना सदर अंचल के कुल 21 एकड़ जमीन जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूर्व में लीज पर दी गई थी, उसे पटना एयरपोर्ट में समानांतर टैक्सी ट्रैक के निर्माण के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को नि:शुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है .

प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सिवान के मौनिया बाबा महावीर झंडा मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के तहत सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा को लेकर गन्ना मूल्य में ?10 प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी किए जाने की स्वीकृति दी गई है. इस पर राज्य सरकार को प्रति साल 70 करोड खर्च करने होंगे.

सरकारी शिक्षक हो जाएं सावधान!

टीचर्स की लिस्ट बनाने का *DM* ने दिया निर्देश, बढ़ने वाली है मुसीबत

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ

पटना. बिहार के आरा में लापरवाह सरकारी शिक्षकों की परेशानी बढ़ने वाली है। जिलाधिकारी ने सभी लापरवाह शिक्षकों की लिस्ट तैयार करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही डीएम ने लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दे दिया है।दरअसल, भोजपुर के डीएम तनय सुल्तानिया ने सही समय पर स्कूल नहीं पहुंचने वाले शिक्षकों की लिस्ट तैयार करने का निर्देश जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया है। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं और असैनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है और कार्यों में तेजी लाने को कहा है। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने बैठक कर मद्याह्न भोजन योजना, शिक्षकों की शत प्रतिशत समय पर उपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सरकार द्वारा छात्रों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की और कई तरह के निर्देश दिए। डीएम ने स्कूली बच्चों के आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनाने के काम में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी कम से कम एक या दो स्कूल को गोद लें और उनपर काम शुरू करें। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

बिहार पर मेहरबान हुई मोदी सरकार

इस मद में *UP* के बाद दी अधिकतम राशि, सम्राट चौधरी ने जताया आभार

चन्दन कुमार चौबे . सिटी चीफ

पटना, चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्सा के रूप में तीसरी बार दोगुना राशि प्राप्त हुई है. इसके लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी का आभार जताया है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि केन्द्रीय करों में हिस्सा के रूप में बिहार को जुलाई 2024 से केंद्र सरकार हर माह

8,960 करोड़ रुपये प्रतिमाह दे रही है, जबकि इस वर्ष 2025 में इस राशि को दोगुणा कर 17,403 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार को अधिकतम राशि उपलब्ध करायी गई है। उन्होंने कहा केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्सा के रूप में तीसरी बार दोगुनी राशि प्राप्त हुई।

सम्राट चौधरी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति प्रदेश की ओर से आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्सा के रूप में देय करों का भुगतान राज्यों को किया जाता है और वर्ष में अतिरिक्त राशि का समायोजन हर साल सिर्फ मार्च के महीने में किया जाता था। वर्तमान एनडीए सरकार ने वर्ष 2021-22 से प्रतिनिधान का समायोजन पूरे वर्ष करना शुरू किया है।

उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में इसी समायोजन के अन्तर्गत माह जून 2024 एवं अक्टूबर 2024 में राशि को दोगुणा कर बिहार को उपलब्ध कराया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि नव वर्ष में माननीया केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस सौगात को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की *NDA* सरकार पूंजीगत व्यय पर खर्च कर न्याय के साथ विकास की यात्रा को और तीव्र करेगी।